



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 2001/श्रावण 26, 1923

No. 581]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 2001/SRAVANA 26, 1923

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 अगस्त, 2001

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2001

का.आ. 791(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2001 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 (इसमें इसके पश्चात् विनियमों के रूप में निर्दिष्ट) में -

(क) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(गग) "विनिवेश" से केन्द्रीय सरकार द्वारा विक्रय अभिप्रेत है, इसके शेयरों या मताधिकारों और / या नियंत्रण का, सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में ।"

(ii) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(झझ) 'सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम' से वह कंपनी अभिप्रेत है जिसमें केन्द्रीय सरकार इसकी इक्विटी पूँजी का 50% या अधिक धारण करती है या कंपनी के नियंत्रण में है ।"

(ख) विनियम 11 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"11(3) विनियम 10, 11 तथा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विनिवेश के मामले में, अर्जनकर्ता जिसने उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों के साथ, सार्वजनिक घोषणा की है, से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शेयरों या मताधिकार के अतिरिक्त अर्जन या नियंत्रण के उत्तरवर्ती प्रक्रम पर एक अन्य सार्वजनिक घोषणा करना अपेक्षित नहीं होगा परंतु कि :-

- (i) अर्जनकर्ता तथा विक्रेता दोनों एक ही अर्जन के सभी प्रक्रमों पर हैं, और
- (ii) अर्जन के सभी प्रक्रमों संबंधी प्रकटीकरण, यदि कोई हों, विनियम 18 के निबंधनों के अनुसार जारी प्रस्ताव पत्र में तथा प्रथम सार्वजनिक घोषणा में किये जाते हैं ।

(ग) विनियम 14 में, उप-विनियम (1) में, परंतुक परिवर्धित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विनिवेश के मामले में, सार्वजनिक घोषणा मर्चेट बैंककार द्वारा किंतु अर्जनकर्ता के विनियम 10 या विनियम 11 में निर्दिष्ट शेयरधारिता या लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पर नियंत्रण के अंतरण की प्रतिशतता से अधिक शेयरों या मताधिकारों के अर्जन हेतु केन्द्रीय सरकार के साथ शेयर क्रय करार या शेयरधारक करार को निष्पादित करने के 4 कार्य दिवसों के अपश्चात् की जायेगी ।"

(घ) विनियम 20 में,

- (i) उप-विनियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण परिवर्धित किया जायेगा; अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विनिवेश के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शेयरों की अंतिम कीमतों के साप्ताहिक उच्च तथा निम्न के औसत के परिकलन हेतु सुसंगत तारीख, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ इसके शेयर अति बारंबार व्यापारित हैं में यथा उत्कथित, तारीख जब केन्द्रीय सरकार (मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्) सफल बोली लगाने वाले का नाम घोषित करती है की पूर्ववर्ती तारीख होगी ।

(ii) उप-विनियम (3) में, स्पष्टीकरण के उप-खंड (i) के पश्चात्, नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(i) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विनिवेश के, मामले में, ऐसे उपक्रम के शेयर बारंबार व्यापारित न हुए समझे जायेंगे, यदि स्टॉक एक्सचेंज पर, मास, जिसमें केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, सफल बोली लगाने वाले का नाम घोषित करती है, के पूर्विक पूर्ववर्ती छह कलेंडर मास के दौरान शेयरों में वार्षिक व्यापारिक व्यापारावर्त सूचीबद्ध शेयरों के दो प्रतिशत (शेयरों की संख्या द्वारा) से कम है । इस प्रयोजन के लिये छह मास कालावधि के दौरान सूचीबद्ध शेयरों की भारित औसत संख्या ली जा सकेगी ।"

(ड) विनियम 22 में, उप-विनियम (16) के पश्चात्, परंतुक परिवर्धित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि विनियमों के अधीन की गयी सार्वजनिक घोषणा के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शेयरों के अर्जन के मामले में, विनियम 23 के उप-विनियम (8) के उपबंध लागू होंगे ।"

(च) विनियम 23 में, उप-विनियम (7) के पश्चात्, नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(8) इस विनियम के उप-विनियम (3) तथा उप-विनियम (6) के खंड (क) के परंतुक में उपबंधित बाध्यताएँ, लागू नहीं होंगी जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों को विक्रय करने का करार इस प्रभाव का खंड का अंतर्विष्ट करता है कि विनियमों के उपबंधों में से किसी के अननुपालन के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शेयर या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्तित किये जायेंगे और अर्जनकर्ता ऐसी शास्ति के दायी होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित की जाये ।"

(छ) विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2क) प्रस्ताव या प्रतियोगी बोली के लिये कोई सार्वजनिक घोषणा इसके पश्चात् नहीं की जायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने अर्जनकर्ता जिसने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शेयरों या मताधिकारों के अर्जन या नियंत्रण हेतु सार्वजनिक घोषणा की है के साथ शेयर क्रय या शेयरधारक करार किया हो ।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/34699/2001]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :-

1. भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997, मूल विनियम, का.आ. सं.124(अ), 20 फरवरी, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
2. तत्पश्चात् शुद्धि-पत्र, का.आ. सं.106(अ), 6 फरवरी, 1998 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ था ।
3. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 28 अक्टूबर, 1998 को, का.आ. सं. 930(अ), भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था द्वारा संशोधित हुआ था ।
4. यह भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 30 दिसम्बर, 2000 को, का.आ. सं. 1178(अ), भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था द्वारा संशोधित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 17th August, 2001

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2001**

S. O. 791(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997.

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2001.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 (hereinafter referred to as the 'Regulations')-

(a) In Regulation 2, in sub-regulation (1),

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(cc) "disinvestment" means the sale by the Central Government, of its shares or voting rights and / or control, in a listed Public Sector Undertaking."

(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

(ii) 'Public Sector Undertaking' means a company in which the Central Government holds 50% or more of its equity capital or is in control of the company."

(b) In Regulation 11, after sub-regulation (2), a new sub-regulation shall be inserted, namely: -

"11(3) Notwithstanding anything contained in Regulations 10, 11 and 12, in case of disinvestment of a Public Sector Undertaking, an acquirer who together with persons acting in concert with him, has made a public announcement, shall not be required to make another public

announcement at the subsequent stage of further acquisition of shares or voting rights or control of the Public Sector Undertaking provided:-

- (i) both the acquirer and the seller are the same at all the stages of acquisition, and
- (ii) disclosures regarding all the stages of acquisition, if any, are made in the letter of offer issued in terms of Regulation 18 and in the first public announcement."

(c) In Regulation 14, in sub-regulation (1), a proviso shall be added, namely :-

"Provided that in case of disinvestment of a Public Sector Undertaking, the public announcement shall be made by the merchant banker not later than 4 working days of the acquirer executing the Share Purchase Agreement or Shareholders Agreement with the Central Government for the acquisition of shares or voting rights exceeding the percentage of shareholding referred to in Regulation 10 or Regulation 11 or the transfer of control over a target Public Sector Undertaking."

(d) In Regulation 20,

- (i) in sub-regulation (2), after clause (d) the following Explanation shall be added ; namely :-

"Explanation: In case of disinvestment of a Public Sector Undertaking, the relevant date for the calculation of the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares of the Public Sector Undertaking, as quoted on the stock exchange where its shares are most frequently traded, shall be the date preceding the date when the Central Government (after receiving the cabinet approval) announces the name of the successful bidder."

(ii) in sub-regulation (3), after sub-clause (i) to the Explanation, a new sub-clause shall be inserted, namely :-

"(ia) In case of disinvestment of a Public Sector Undertaking, the shares of such an undertaking shall be deemed to be infrequently traded, if on the stock exchange, the annualised trading turnover in the shares during the preceding six calendar months prior to the month, in which the Central Government, after receiving the cabinet approval, announces the name of the successful bidder, is less than two percent (by the number of shares) of the listed shares. For this purpose the weighted average number of shares listed during the six months period may be taken".

(e) in Regulation 22, after sub-regulation (16), a proviso shall be added, namely:-

"Provided that in case of the acquisition of shares of a Public Sector Undertaking pursuant to a public announcement made under the

Regulations, the provisions of sub-regulation (8) of Regulation 23 shall be applicable.”

(f) in Regulation 23, after sub-regulation (7), a new sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(8) The obligations provided for in the proviso to clause (a) of sub-regulation (3) and sub-regulation (6) of this regulation, shall not be applicable where the agreement to sell shares of a Public Sector Undertaking contains a clause to the effect that in case of non-compliance of any of the provisions of the Regulations, the shares or the control of the Public Sector Undertaking shall revert back to the Central Government and the acquirers shall be liable to such penalty as may be imposed by the Central Government.”

(g) in Regulation 25, after sub-regulation (2), a new sub-clause shall be inserted, namely:-

“(2A) No public announcement for an offer or competitive bid shall be made after the Central Government has entered into a Share Purchase or Shareholders' Agreement with the acquirer who has made the public announcement for acquisition of shares or voting rights or control of a Public Sector Undertaking.”

[F. No. SEBI/LE/34699/2001]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :-

- (1) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, the principal regulation, was published in the Gazette of India on February 20, 1997, vide SO No. 124(E).
- (2) Subsequently a Corrigendum was published in the Gazette of India Extraordinary on February 6, 1998, vide S.O. No 106(E).
- (3) It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 1998 which was published in the Gazette of India on October 28, 1998, vide S.O. No 930(E).
- (4) It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2000 which was published in the Gazette of India on December 30, 2000, vide S.O. No. 1178(E).

